College, Calicut, for the year 1992-93, together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above College.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-6170/94]

(iv) (a) Annual Reports and Accounts of the Visvesvaraya Regional College of Engineering, Nagpur for the year 1992-93, together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above College.

(c) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-6169/84]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Regional Engineering College, Rourkela, for the year 1992-93, together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above College.

(c) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-6168/94]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Legal Services Authorities (Amendment) Bill, 1992

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"I am directed to inform you that the Legal Services Authorities (Amendment) Bill, 1992, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd March, 1992, has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 4th August, 1994, with the following amendments:—

Enacting Formula

1. Page 1, line 1,—

for "Forty-third" *substitute* "Forty-fifth"

Clause 1

2. Page 1, line 4,—

for "1992" *substitute* "1994"

2. I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisons of rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha with the request that the concurrence of Rajya Sabha in the said amendments be communicated to Lok Sabha."

Madam, I lay a copy of the amended Bill on the Table.

REFERENCES

Re. State of pandemonium prevailing in the house

THE DEPUTY CHAIRMAN: Statement regarding Government Business.

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, is there any break-through in the stalemate? You are not giving any happy news to the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Home Minister is going to make a statement.

SHRI P. UPENDRA: How long will it continue like this? The Home Minister may make a statement on the bomb blasts. What about the blast here?

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Something should be done urgently, Madam.

SHRI P. UPENDRA: We would like to know whether something is being done or whether there is a complete stalemate or whether there is any dialogue going on or not. How long will we continue the House like this? We cannot continue the House like this.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, एक मिनट का समय लूंगा। बम्बई में जो बम विस्फोट हुआ है उसके मुख्य मुलजिम के बारे में गृह मंत्री जी बयान देंगे। लेकिन यह सदन की क्या हालत है? उपेन्द्र जी ने जो बात उठाई है यह सच है कि हम लोग बहुत दहशत में हैं। हम लोगों के गांव में कोई भी मकान गिर जाता है, आधा होता है तो उसको हम लोग भूताह मकान कहते हैं। यह सच नहीं है कि हम लोग राज्य सभा और लोक सभा के भूताह मकान की तरह हैं? कुछ आत्मायें बाहर भटक रही हैं और कुछ आत्मायें यहां दहशत में बैठी हुई हैं। कोई राष्ट्रपति भवन से लेकर पोर्टिको तक भटकती हुई दिखाई देती हैं। यह एक चरित्र ही है। कुछ लोग यहीं दहशत में बैठे हुए हैं। यहां दो-चार मंत्री होंगे ज्यादा दहशत में होंगे कि कहीं हमारा नम्बर न आ जाए लेकिन बगल के सदन वाले सारे सदस्य दहशत में हैं कि पता नहीं कब हमारी मेम्बरी खत्म हो जाए। इतनी गम्भीर समस्या है कि हम लोग भूताह की तरह से सदन में बैठे हुए हैं। माननीया यह सच नहीं है कि जो चले गये हैं उनसे हमारी शिकायत है। बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं होता कि जो लोग बैठे हैं वे दोषमुक्त हैं और उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उनकी भी कहीं न कहीं पर गलती है तो इस गलती को कबूल करें। मैं उन लोगों को अच्छा नहीं मानता जो अयोध्या राम जन्मभूमि के सवाल पर संसद की मर्यादा को, सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा को, राष्ट्रीय एकता परिषद् की मर्यादा को बलाय ताक पर रखते हैं। मैं जानता हूं वे संसद् की मर्यादा कहां तक रखते हैं। लेकिन जो लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं, सत्ता में बैठे हैं, संसद की मर्यादा की रखवाली करते हैं एक कमेटी की रिपोर्ट में जो लोग दोषी हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। जवाहर लाल जी के जमाने में, टी.-टी. कृष्णामचारी के जमाने में छागला कमेटी की रिपोर्ट में जो लोग दोषी माने गये थे जवाहर लाल जी ने उनको हटा दिया था। क्यों नहीं दोषी लोगों को हटाया जा रहा है? कौन दोषियों को बचाने के रास्ते में आ रहा है? यह नेहरू की पार्टी है, यह गांधी की पार्टी हैं, यह इन्दिरा गांधी की पार्टी है। क्यों बचाया जा रहा है दोषी लोगों को? इस भूताह मकान में बैठ कर बहस करें यह अच्छी बात नहीं होगी। मैं चाहूंगा नेता सदन बम विस्फोट पर बयान देने के पहले इस सदन के अंदर जो विस्फोट हो गया है उस पर बयान दें। आपके माध्यम से चेयरमैन साहब तक और लोक सभा के स्पीकर साहब तक अगर हमारी बात पहुंचा सकें तो पहुंचा दें। पीड़ा होती है यहां बैठने में। हम यहां बैठे हैं हम सरकारी पार्टी में नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए। हम किसी की मदद में नहीं बैठे हैं। हम विरोधी पार्टी के हैं। लेकिन जो लोग इंसान-इंसान में नफरत और साम्प्रदायिकता की बुनियाद पर यहां बैठे हैं उनसे हम घृणा करते हैं। इस तरफ इनसे विरोध है और दूसरी तरफ उनसे घृणा है। उनके हाथ में भी हम खेल नहीं जाने देना चाहते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विरोधी पक्ष के साथ बैठकर अभी भी बातचीत से कोई रास्ता निकालिये। अड़ियल रूप से जनतंत्र का, पंचायत राज का कोई रास्ता हल नहीं हुआ है। इतना ही निवेदन मुझे करना है।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, may I raise an important issue?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will call you.

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, to what extent will we go on like this? (*interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I wish I had an answer.

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI: How far will this deadlock go on? Actually, the Parliament is not functioning in the absence of the Opposition. Something has to be done urgently to bring them back. From political conciliation we have come to a stage of political confrontation. It is very unfortunate.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, दो दिन पहले भी यह प्रश्न उठा था। श्री उपेन्द्र जी ने इस प्रश्न को यहां पर उठाया था और आज माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने यह प्रश्न उठाया है। यह जो प्रश्न है यह देश और संसद के लिए एक गंभीर प्रश्न है। विपक्ष की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। देश में और देश के बाहर यह अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। मेरी राय में यह संसदीय परम्परा के प्रतिकूल काम हो रहा है। मैं ज्यादा लम्बा भाषण न करके, आपके माध्यम से देश के प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी हठवादिता त्याग दें और इस पर गंभीरता से विचार करें। यह देश की संसदीय परम्परा का सवाल है, देश के संविधान का सवाल है और इस देश की एकता और अखंडता का सवाल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हठवादिता त्यागकर कोई ऐसा उपाय निकालें, कोई ऐसा सम्मानजनक हल निकालें जिससे समस्या का हल हो सके। मैं विपक्ष से भी कहूंगा जो आज सदन में नहीं है, जो बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं कि वे भी संसद की गरिमा को बनाये रखने के लिए, संसद के सम्मान को बनाये रखने के लिए सम्मानजनक ढंग से वार्ता करके पुन: संसद में आयें। मेरा उन लोगों से यह अनुरोध है।

उपसभापति : दो दिन पहले उपेन्द्र जी ने यह सवाल उठाया था और कल भी उठाया। इसका नतीजा निकला और होम मिनिस्टर साहब जो इस हाउस के लीडर भी है, उन्होंने इस पर अपनी राय दी। हमने भी अपनी राय दी थी। सभी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाउस में कोई नहीं है। प्रिसाइडिंग आफिसर को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हाउस खाली है।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam,......

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minue, Let me speak firs. Had you asked me earlier, I would have allowed you. I will allow you.

सवाल यहां यह है कि जो बातचीत चल रही है, बातचीत तो कहीं न कहीं चल रही है, कुछ न कुछ हल तो निकलेगा। मैं इस उम्मीद में हूं। क्योंकि जो लोग बाहर भी बैठे हैं वे भी कुछ सोचते होंगे, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। सभी लोग अपनी-अपनी तरफ से कोशिश में हैं। हम से पूछा गया कि क्या हुआ, कब आ रहे हैं, इसकी तो हम सीमा नहीं बांध सकते, टाईम बाउंड प्रोग्राम I cannot announce. But definitely, I am hopeful that something will come out and should come out. All of us should participate to bring in some sort of an agreement. Yes, Mr. Ravi.

SHRI VAYALAR RAVI; I think there is no point left because you have already made your observation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you ike you ca nsay something because you are from the ruling party. My remarks were from the Chair.

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, I share the sentiments expressed by the hon. Members, Shri Upendra, Shri Mishra and others. But, at the same time, I am at a loss to understand this. The whole problem started like this. First, we came to know that there would be a discussion on the Callrng Attention Motion. Thereafter, we understood that it would be under rule 168. The Government, as I understand, is not [illegible]

on prestige. The Government agreed to the proposal of the Opposition. But, unfortunately, friends from the other side switched over to other proposals. when the Government agreed to their proposal, they made another demand. Let the nation and the people know what exactly the Opposition wants and what proposal they made before the Government. Once the Government has agreed to their proposal, it is not fair on the part of the Opposition to go back on that proposal. So, Madam, I believe that nobody is standing on prestige and, definitely, the Government, if I understand correctly, wants everybody, including the Opposition in Parliament and wants that this Parliament be run with full quorum with all the Members present. I hope that my friends will correct any kind of wrong impression being created in the country that the ruling party or anybody else, for that matter, is standing on prestige.

Re: Demand to withdraw ATR Report

SHRI MADAN BHATIA (Nominated) Madam, I would like to place before the hon. Members one fundamental issue and that is the right of each and every individual Member to either express his assent or express his dissent. Once the ATR was placed on the Table of the House, it became the property of Parliament and, through Parliament, it became the property of the people of India. It is the Constitutional right of not only each Member but also of every citizen of this country to have the opportunity of access to a document which has become part of the record of Parliament and therefore, the record of the people of India. This is the property of the people of India: Even the Presiding Officer of either this hon. House or the Lok Sabha does not have the power to allow withdrawal of the Report leading to a mutilation of the record of Parliament and the record of the people of India because it is the property of the people of India. This Report was placed on the Table of the House with the consent of the Members of Parliament. Members of Parliament are the representatives of the people. It is the representatives of the people alone who can, collectively, decide whether this will continue to remain part of the record of Parliament and whether it will remain on the record of Parliament or not. Neither the Opposition has got a right to say to the Government "Withdraw this report", nor the Government has got a right to say, we withdraw the Report. This will amount to a total mutilation of the record of Parliament.... (*Interruptions*)

SHRI P. UPENDRA: It is not a question of legally.. (*Interroptions*) Why cannot the Government withdraw? They have withdrawn Constitutional amendments several times... (*Interruptions*)

SHRI MADAN BHATIA: I am expressing my view... (*Interruptions*)

SHRI P. UPENDRA: It is not correct.

SHRI MADAN BHATIA: Under the Constitution, every Member has been vested with the Constitutional right of freedom of expression. If any demand is made by any Member or any political party that they do not agree with this Report and that this Report should be withdrawn, then I, as an individual Member, who has been vested by the Constitution the fundamental right of freedom of expression, have also a right to dissent from this view. This opportunity cannot be denied to me. I appeal strongly to the Members of those political parties, who say that this Report should be withdrawn without a discussion, ',Please respect my right under the Constitution and let me have the voice to say that I dissent from your view." This is a right belonging not only to me but this is a right belonging to each and every Member of Parliament and that right cannot be stifled, that right of each and every Member of Parliament cannot be stifled by one political party or two political parties. It will be a total travesty of the Constitution. Lastly Madam, I would say that the whole Parliament can function only by debate, only by discussion. If you stifle the discussion, if you stifle the debate, you are